



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 1, 2008/वैशाख 11, 1930

No. 156]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 1, 2008/VAISAKHA 11, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2008

विषय : रूस और चीन जन. गण. से अलॉय और गैर-अलॉय स्टील बिलेट्स, बार और राउंड्स के कतिपय ग्रेडों के भारत में आयात के विरुद्ध लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा—जाँच की समाप्ति ।

सं. 15/6/2008-डीजीएडी.—यतः मै. कल्याणी स्टील्स लि. ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली में रिट याचिका (सिविल) सं. 15945/06 के रूप में एक सिविल रिट याचिका दायर की थी और दिनांक 3.12.2007 के निर्णय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार नियमावली के नियम 23 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्णायक समीक्षा किया जाना अपेक्षित है ।

2. और यतः माननीय न्यायालय ने माना है कि दिनांक 1 फरवरी, 2008 से रूस और चीन से किए गए संबद्ध वस्तु के सभी आयातों की केन्द्र सरकार द्वारा अनंतिम रूप से निकासी की जानी चाहिए और इस बीच केन्द्र सरकार को यह निर्धारित करने के लिए एक समीक्षा करनी चाहिए कि क्या दिनांक 25 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क 26 दिसम्बर, 2005 के बाद पाँच वर्ष की अवधि के बाद जारी रहना चाहिए । माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी माना है कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा यह पाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9क(5) के पहले परन्तुक की अपेक्षाएं पूरी होती हैं और पाटनरोधी शुल्क जारी रहना चाहिए तो घरेलू उद्योग के हितों की संरक्षा 1 फरवरी, 2008 से अनंतिम आकलन द्वारा की जाएगी और आगे यह निर्देश दिया कि केन्द्र सरकार यथासंभव शीघ्रता से समीक्षा पूरी करेगी ।

3. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में, 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली को ध्यान में रखते हुए; उपर्युक्त नियमों

के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना द्वारा “अलॉय और गैर-अलॉय स्टील बिलेट्स, बार और राउंड जिनका व्यास 70 मिमी से 250 मिमी हो तथा जो आईएस विनिर्देशनों अथवा आईएस मानकों के समतुल्य किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशन के अनुपालन में हों, की कतिपय किस्मों/ग्रेडों” के आयातों पर पाटन के जारी रहने या पाटन एवं क्षति पुनरावृत्ति होने की जाँच हेतु एक समीक्षा जाँच शुरू की थी।

4. और जबकि घरेलू उद्योग को निर्धारित रूप एवं तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और वर्तमान समीक्षा से संबंधित अपने विचारों से प्राधिकारी को अवगत कराने के लिए अलग-अलग लिखा गया था और उन्हें इस मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) का समय दिया गया था और यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अपूर्ण होती है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

5. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कथित पाटन और क्षति के संबंध में जाँच माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर शुरू हुई थी और घरेलू उद्योग ने 40 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्राधिकारी के समक्ष इस बात का आकलन करने के लिए कोई दस्तावेजयुक्त याचिका प्रस्तुत नहीं की है कि क्या पाटन और क्षति के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. कल्याणी स्टील्स लि. और मै. महाराष्ट्र सीमलैस लि. से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें मामले से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय और देने की माँग की गई है लेकिन चार सप्ताह की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने पर भी पूर्ण रूप से दस्तावेजयुक्त याचिका प्राप्त नहीं हुई है और इन दोनों प्रतिवादी उत्पादकों को सात दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराने के लिए जाँच समाप्ति संबंधी एक नोटिस दिया गया था जो इसके बाद भी आज की तारीख तक प्राप्त नहीं हुई है।

6. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) में यह व्यवस्था है कि अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क उसके अधिरोपण की तारीख से पाँच वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते कि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार की यह राय हो कि ऐसे शुल्क को हटाए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। वर्तमान मामले में, चूँकि रिकार्ड में यह सिद्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं है कि वर्तमान शुल्क को हटाए जाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, इसलिए प्राधिकारी पूर्व में लागू किए गए पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाए जाने की सिफारिश करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्राधिकारी एतद्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 15/6/2008-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई जाँच, इस मामले से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करते हैं और यह सिफारिश करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत नहीं है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st May, 2008

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed against imports into India of certain grades alloy and non-alloy steels billets, bars and rounds from Russia and China PR.—Termination of Initiation.

No. 15/6/2008-DGAD.—Whereas M/S Kalyani Steels Ltd. filed a civil writ petition in Hon'ble High Court of Delhi as Writ Petition (Civil) No.15945/06, and as per direction of the Hon'ble Court vide judgment dated 3.12.2007, Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the Rules.

2. AND Whereas the Hon'ble Court held that All imports of the subject goods made from Russia and China with effect from 1st February, 2008 should be provisionally cleared by the Central Government and in the meanwhile, the Central Government should carry out a review to determine whether the anti-dumping duty imposed by the Notification dated 25th June, 2001 should continue beyond the period of five years from 26th December, 2005 onwards. The Hon'ble Court in its Judgment also held that if it is found by the Central Government that the requirements of the first proviso to Section 9A (5) of the Act are met and anti dumping duty should continue, then the provisional assessments made with effect from 1st February, 2008 will take care of the interests of the domestic industry and further directed that the Central Government will complete the review as expeditiously as possible.

3. Pursuant to the said Order of the Hon'ble High Court, Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules 1995, thereof, the Designated Authority (hereinafter also referred to as Authority), under the above Rules, initiated the review investigation to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of "certain types/grades of alloy and non alloy steel billets, bars and rounds having 70 mm to 250 mm diameter conforming to IS specification or *any* other international specification equivalent to IS standards". Vide notification dated 23rd January 2008,

4. And whereas the domestic industry were addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority relating to the present review and were allowed forty days (40 days) from the date of publication of the review notification to submit the information related to the case and it was also made clear that if no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

5. The Authority notes that the investigation into alleged dumping and injury was initiated based upon the directions of the Hon'ble High Court and the domestic industry has not come up, within the stipulated period of 40 days, with a documented petition for the

Authority to assess whether there is sufficient evidence of dumping and injury. The Authority further notes that a request was received from M/S Kalyani Steels Ltd. And M/s Maharashtra Seamless Ltd. seeking an extension of time by four weeks to submit information related to the case but the fully documented petition was not received even at the expiry of this four weeks extended time and a notice of termination was served on both these responding producers to provide the information within 7 days time thereafter which has also not been forthcoming till date.

6. Section 9A(5) of the Customs Tariff Act provides that the anti-dumping duty imposed shall, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, **provided** that the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In the instant case, since there is no information on record to establish that the cessation of the present duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority does not consider it appropriate to recommend extension of the anti dumping duties earlier imposed. Therefore, the Authority hereby terminates the investigation initiated vide notification No.15/6/2008-DGAD dated 23rd January 2008, all proceedings connected with this case and recommends that the anti dumping duties need not be extended further.

R. GOPALAN, Designated Authority